जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

जालोर

Rashtradoot

फोनः- 226422, 226423 फैक्सः- 02973-226424 वर्षः 21 संख्याः 24 प्रभात जालोर, शनिवार 2 मई, 2026 पो. रजि. /RJ/SRO/9640/2022-24 पृष्ठ 8 मूल्य 2.50 रु.

सभी प्रशंसक व दुश्मन, यह ही चाहते हैं, वेणुगोपाल केरल के मु.मंत्री बने

पर, वेणुगोपाल केरल तभी जाना चाहते हैं, जबकि कांग्रेस केरल में 85 का आंकड़ा पार कर ले, जिससे कांग्रेस की सरकार इतनी मजबूत हो कि भाजपा उसे तोड़ न सके पूरे साम-दाम-दण्ड-भेद लगाने के बावजूद

- रेणु मित्तल -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -

नई दिल्ली, 1 मई। कांग्रेस पार्टी की नज़रें पूरी तरह से एआईसीसी महासचिव और संगठन प्रभारी के. सी. वेणुगोपाल पर टिकी हुई हैं।

मुख्य सवाल यह है कि वेणुगोपाल जाएंगे या नहीं?

क्या वे केरल में अगले मुख्यमंत्री बनेंगे, जहां एग्ज़िट पोल्स ने कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत दिखाया है?

वेणुगोपाल को पसंद करने वाले और उनकी प्रशंसा करने वाले लोग उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं।

और जो लोग उन्हें पसंद नहीं करते, वे भी चाहते हैं कि वे केरल जाएं और राहुल गांधी के सबसे भरोसेमंद हाथ के रूप में पिछले 7 साल से संगठन, नियुक्तियों, संसद, राहुल गांधी की ओर से गठबंधनों और रणनीतिक निर्णयों को

- कांग्रेस में एक बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि अगर वेणुगोपाल केरल जाते हैं, तो दिल्ली में उनकी जगह कौन आएगा। क्योंकि, गत सात साल से वेणुगोपाल ही राहुल की ओर से सभी निर्णय ले रहे थे कांग्रेस में।
- भंवर जितेन्द्र सिंह का नाम चल तो रहा है, क्योंकि वे गांधी परिवार के निकट हैं, पर, उनका प्रदर्शन व ट्रैक रिकॉर्ड काफी निराशाजनक रहा है अब तक।
- और, राहुल चाहते हैं, नया महासचिव ऐसा व्यक्ति हो, जो 2029 के लोकसभा चुनाव की दृष्टि से हर राज्य की राजनीति और खेमेबाजी को अच्छी तरह से समझ ले तथा भाजपा के शीर्षस्थ नेताओं से भी बातचीत कर, रोजमर्रा के काम निकलवा ले और इससे भी जरुरी बात है कि यह व्यक्ति सभी मामलों में गांधी परिवार के हित की भी सुरक्षा कर सके।
- इतनी जटिलताओं से निपटने वाला अभी तक तो कोई नेता नज़र नहीं आया है, कांग्रेस में।

नियंत्रित करने वाला व अपना स्थान खाली करें।

वे राहुल गांधी के 'यस मैन' हैं और राहुल गांधी की हिदायत के अनुसार काम करते हैं।

इस प्रक्रिया में, उन्होंने पार्टी में अपनी टीम और विभिन्न राज्यों में कुछ समूह बनाए हैं, जो उनके प्रति वफादार

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

सुप्रीम कोर्ट ने खेड़ा को अग्रिम जमानत दी

- जाल खंबाता -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -

नई दिल्ली, 1 मई। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को अग्रिम जमानत दे दी। यह मामला असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा की पत्नी रिंकी भुइयाँ सरमा के खिलाफ कथित झूठे बयानों से जुड़े फर्जीवाड़े और मानहानि के आरोपों से संबंधित है।

यह राहत उस समय आई है, जब उच्चतम न्यायालय ने एक दिन पहले खेड़ा की उस याचिका पर अपना फैसला

- सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा के वकील अभिषेक मनु सिंघवी की यह दलील स्वीकार की कि इस केस में हिरासत की जरूरत नहीं है तथा आरोप ज़मानती हैं।

सुरक्षित रख लिया था, जिसमें उन्होंने गुवाहाटी उच्च न्यायालय द्वारा उन्हें गिरफ्तारी से पहले जमानत देने से इनकार किये जाने को चुनौती दी थी। न्यायमूर्ति जे.के. महेश्वरी और ए.एस. चंदुरकर की बैंच ने आदेश जारी करने से पहले दोनों पक्षों की विस्तृत दलीलें सुनी थीं।

खेड़ा की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने तर्क दिया कि

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

चुनाव आयोग ने कोलकाता के सभी स्ट्राँग रूम को अभेद्य दुर्ग बनाया

ममता बनर्जी के एक स्ट्राँग रूम तक जाने के बाद चुनाव आयोग ने यह कदम उठाया

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 1 मई। कोलकाता पुलिस ने कोलकाता के सात क्षेत्रों में किसी भी तरह की भीड़ जुटाने की कवायद पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये वे क्षेत्र है, जहाँ विधानसभा चुनाव में डाले गए मतों की गिनती होनी है। यह कदम पिछले रात हुई अतिनाटकीय घटनाओं के बाद उठाया गया, जो बीती रात दो काउन्टिंग केन्द्रों पर तृणमूल कांग्रेस द्वारा संदिग्ध गतिविधियों के आरोपों के कारण हुई थीं।

पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल ने तृणमूल के आरोपों को पहले ही खारिज कर दिया है।

पुलिस द्वारा लागू किए गए निषेधाज्ञा आदेश निम्नलिखित क्षेत्रों में है: शहीद खुदीराम बोस रोड, जज कोर्ट रोड, जादवपुर, डायमंड हार्बर रोड, लॉर्ड सिन्हा हॉल, नरेश मित्र सरणी (बेलटाला रोड), प्रथमेश बरुआ सरणी।

पिछली रात, भाजपा और तृणमूल कार्यकर्ताओं के बीच कोलकाता के

- कोलकाता पुलिस ने शहर के उन सभी सात क्षेत्रों में भीड़ जुटने पर सख्त रोक लगा दी है, जहाँ मतगणना होनी है।
- बुधवार रात तृणमूल कांग्रेस ने स्ट्राँग रूम में ईवीएम तथा पोस्टल बैलेट में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया था। जिसे प.बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज अग्रवाल ने खारिज कर दिया और कहा कि सभी स्ट्राँग रूम सुरक्षित है और तालाबंद हैं, और जिस स्ट्राँग रूम में पोस्टल बैलेट रखे हैं, वहाँ उन्हें व्यवस्थित किया जा रहा था।
- नेताजी इंडोर स्टेडियम के काउंटिग सैंटर पर भाजपा और तृणमूल समर्थकों के बीच टकराव भी हुआ, दोनों पक्षों ने जमकर नारेबाजी की।

नेताजी इंडोर स्टेडियम के गिनती केन्द्र के बाहर टकराव हुआ। तृणमूल उम्मीदवार कुणाल घोष और शशि पांजा मतगणना केन्द्र के गेट के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने नारे लगाए, जिससे एक छोटा सा संघर्ष हुआ।

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी सखावत मेमोरियल गिनती केन्द्र के स्ट्रांग रूम के पास आई थीं।

राज्य के शीर्ष चुनाव अधिकारी अग्रवाल ने तृणमूल के आरोपों को खारिज करते हुए कहा, "खुदीराम अनुशीलन केन्द्र के स्ट्रांग रूम में उत्तरी कोलकाता की सात विधानसभा सीटों

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

तीन सप्ताह में छोड़ो पांचना बांध से नहरों में पानी : हाईकोर्ट

हाईकोर्ट ने अदालती आदेशों की पालना के बजाय समय मांगने पर अधिकारियों को फटकार लगाई

-यादवेन्द्र शर्मा-

जयपुर । राजस्थान हाईकोर्ट ने करौली जिले के पांचना बांध से जुड़ी नहरों में 3 सप्ताह के भीतर बांध का पानी छोड़ने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने अदालती आदेश की पालना के बजाय अधिकारियों को और समय मांगने पर फटकार लगाते हुए चेतावनी दी कि न्यायालय के धैर्य की परीक्षा न लें, आदेश की तीन सप्ताह में पालना की जाए। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा के नेतृत्व वाली खंडपीठ ने कांग्रेस विधायक रामकेश मीणा की जनहित याचिका पर यह आदेश दिया। याचिकाकर्ता ग्रामोत्थान संस्था की ओर से अधिवक्ता दीपक शर्मा ने अदालत में पैरवी की।

हाईकोर्ट सुनवाई के दौरान जलदाय विभाग (पीएचईडी) के इंजीनियर्स मौजूद थे। हाईकोर्ट ने उनसे पानी न खोलने का कारण पूछा, तो जलदाय विभाग ने कहा कि राज्य

- राज्य सरकार की ओर से कोर्ट में एक गोपनीय ''एडीजे रिपोर्ट'' न्यायाधीशों के समक्ष प्रस्तुत की गई, जिसमें कहा गया कि, यह रिपोर्ट सिर्फ अदालत को यह दर्शाने के लिए है कि, अगर फिलहाल पानी छोड़ दिया गया और केवल एक ही जाति विशेष से जुड़े गांवों को पानी पहुंचेगा तो वहां कानून-व्यवस्था बिगड़ने का खतरा है।
- इस पर अदालत ने कहा कि, कानून-व्यवस्था संभालना राज्य सरकार का काम है, लेकिन इसकी आड़ में अदालती आदेशों की अवमानना नहीं की जा सकती।

सरकार को पानी छोड़ने की व्यवस्था करने के लिए चार से पांच महीने का समय दिया जाए। उन्होंने कहा कि अभी पानी छोड़ने से रबी फसल को फायदा नहीं होगा। इस पर अदालत ने फटकारते हुए कहा कि, जलदाय विभाग बहानेबाजी छोड़े, पानी सिर्फ सिंचाई के लिए ही नहीं, बल्कि मवेशियों समेत अन्य कार्यों के लिए भी जरूरी है। इसके बाद राज्य सरकार की ओर से एक गोपनीय "एडीजे रिपोर्ट" न्यायाधीशों को दिखाने के लिए प्रस्तुत की गई। राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि यह रिपोर्ट सिर्फ अदालत को यह दर्शाने के लिए है कि, अगर फिलहाल पानी छोड़ दिया गया और केवल एक ही जाति विशेष से जुड़े गांवों को पानी मिला तो

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

हाई कोर्ट ने जिंदा बम प्रकरण में सजा स्थगित करने से इंकार किया

जयपुर, 1 मई। राजस्थान हाईकोर्ट ने 13 मई, 2008 को शहर में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के बीच जिंदा मिले बम को लेकर विशेष अदालत की

- राजस्थान हाई कोर्ट की खंडपीठ ने अभियुक्तों की अपीलें खारिज की।

ओर से अभियुक्तों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा को अपील के निस्तारण तक स्थगित करने से इनकार कर दिया है। इसके साथ ही, अदालत ने अभियुक्तों की ओर से दायर सजा स्थगन प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया है। जस्टिस इन्द्रजीत सिंह और जस्टिस भुवन गोयल की खंडपीठ ने यह आदेश शाहबाज हुसैन और मोहम्मद सरवर आजमी की ओर से अपील में दायर प्रार्थना पत्र को खारिज करते हुए दिए।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

ईरान वॉर से अमेरिका में ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग में भारी कमी हुई

रॉयटर्स/इप्सॉस सर्वे के अनुसार, ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग मात्र 36 प्रतिशत ही रह गई है और मात्र 26 प्रतिशत ही ईरान वॉर पर उनका समर्थन करते है

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो।

नई दिल्ली, 1 मई। राष्ट्रपति के रूप में डॉनल्ड ट्रम्प को दूसरा कार्यकाल एक अशांत चरण में प्रवेश कर रहा है, जिसमें ईरान में चल रहे युद्ध ने केवल भू-राजनीतिक खामियों को ही उजागर नहीं किया, बल्कि घरेलू राजनीतिक संकट को भी बढ़ा दिया है। टैरिफ और आर्थिक प्रबंधन से शुरु हुई आलोचना अब विदेश नीति को लेकर बढ़ते असंतोष में बदल गई तथा प्रशासन को सबसे चुनौतीपूर्ण दौर में धकेल दिया है।

फरवरी में शुरू हुए ईरान संघर्ष ने वैश्विक तेल आपूर्ति को बाधित किया और ईंधन की कीमतों को बढ़ा दिया और यह ट्रम्प के नेतृत्व की केन्द्रीय परीक्षा बन गया है। जनता का समर्थन जुटाने के बजाय, यह युद्ध उनकी अनुमोदन रेटिंग

- सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मात्र 26 प्रतिशत अमेरिकन ही मानते हैं कि ईरान पर सैन्य कार्यवाही पर लगी लागत नुकसान का सौदा नहीं है।
- ट्रंप को उम्मीद थी कि ईरान वॉर उनके पक्ष में जनता को एकजुट कर देगा, पर, वॉर ने उनकी लोकप्रियता में भारी कमी कर दी है और इस बात से ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी में भी चिंता की लहर है और पार्टी में भी युद्ध के प्रति अब ऊब व थकान के संकेत नज़र आ रहे हैं।
- विदेश नीति के मोर्चे पर भी ट्रंप के प्रति असंतोष बढ़ा है, मात्र 39 प्रतिशत ही ट्रंप की विदेश नीति को सही मानते हैं। ईरान वॉर पर ट्रंप की कार्यशैली से डेमोक्रेट्स ही नहीं रिपब्लिकन्स भी नाखुश हैं।
- ईरान वॉर के कारण तेल की बढ़ती कीमतों और महँगाई भी एक बड़ा कारण है, ट्रंप की लोकप्रियता घटने का।

में गिरावट को तेज करने वाला प्रतीत हो रहा है, जिससे रिपब्लिकन पार्टी के भीतर भी चिंता बढ़ रही है।

हालिया मतदान डेटा इस समस्या के पैमाने को दर्शाता है। रॉयटर्स/इप्सोस के एक सर्वेक्षण के अनुसार, ट्रम्प की कुल अनुमोदन रेटिंग केवल 36 प्रतिशत है, जबकि केवल 32 प्रतिशत लोग ईरान संघर्ष में उनके प्रबंधन को सही मानते हैं। और भी ध्यान देने योग्य बात यह है कि केवल 26 प्रतिशत अमेरिकी मानते हैं कि सैन्य कार्यवाही पर जो खर्च हुआ है, वह फायदे का सौदा है। इससे जाहिर है अधिकांश लोग, युद्ध के उद्देश्यों और परिणामों के प्रति गहरी शंका रखते हैं।

वृहद सर्वेक्षण भी इसी प्रकार की निराशाजनक तस्वीर पेश करते हैं। एप-

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

प. बंगाल - 15 मतदान केन्द्रों पर आज पुनः वोट पड़ेंगे

नई दिल्ली, 01 मई । चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के दूसरे चरण में 29 अप्रैल को हुए मतदान के बाद दो विधानसभाओं के 15 मतदान केन्द्रों पर दोबारा मतदान शनिवार को कराने का फैसला किया है।

आयोग की ओर से जारी आधिकारिक पत्र के अनुसार, संबंधित

- इनमें से 11 मतदान केन्द्र मगरहाट पश्चिम के तथा 4 डायमंड हार्बर के हैं।

रिटर्निंग अधिकारियों और प्रेक्षकों की रिपोर्ट में मतदान प्रक्रिया में अनियमितताओं की आशंका जताई गई थी जिसके बाद यह कदम उठाया गया। पुनर्मतदान के लिए मगरहाट पश्चिम के 11 और डायमंड हार्बर के 4 मतदान केंद्र हैं। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, सभी चिन्हित मतदान केन्द्रों पर 2 मई को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा।

जाने माने इकॉनमिस्ट जेफ्री सैक्स इस साल के अंत तक 250 स्कॉलर्स व आध्यात्मिक नेताओं को बनारस में एकत्रित करना चाहते हैं

सैक्स का मानना है, वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय संकट, क्लाइमट चेंज से आर्थिक असामनता केवल आर्थिक नीतियों व मार्केट आधारित सोच से हल नहीं हो पाएगा, इसके लिए नैतिक फ्रेमवर्क चाहिए

- सुकुमार साह -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -

नई दिल्ली, 1 मई। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जेफ्री सैक्स वर्ष के अंत तक वाराणसी में लगभग 250 विद्वानों और आध्यात्मिक नेताओं को एकत्रित करने की योजना बना रहे हैं, ताकि शांति और भाईचारे का संदेश फैलाया जा सके। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में दिए गए उनके बयान उनके व्यापक और लंबे समय से चल रहे प्रयास का हिस्सा हैं, जिसमें वे अर्थव्यवस्था, नैतिकता और सतत विकास को नैतिक नेतृत्व के साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं।

संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों पर गहन रूप से काम कर चुके अर्थशास्त्री सैक्स का तर्क है कि अंतर्राष्ट्रीय संकट संपर्क, जलवायु परिवर्तन से लेकर असमानता तक को केवल नीतियों और बाजारों के माध्यम से हल नहीं किया जा सकता; इसके लिए साझा मूल्यों और नैतिक ढांचे का पुनरुद्धार भी आवश्यक है।

वाराणसी का चयन जानबूझकर और प्रतीकात्मक है। यह दुनिया के उन सबसे पुराने शहरों में से एक है, जो

- इस तथाकथित समागम के लिए, वाराणसी का चयन भी, सैक्स के अनुसार, काफी उचित है। क्योंकि वाराणसी, पृथ्वी पर लगातार रिहायश की दृष्टि से शायद सबसे पुराना शहर है तथा सदा से अभी तक सांस्कृतिक ज्ञान का केन्द्र रहा है।
- और आज के युग में हर देश की सभी सोच व चिंतन अपने संक्रीण राष्ट्रीय हित तक सीमित है। बनारस में यह समागम, जहाँ हिंदू, बौद्ध, ईसाई, इस्लामिक सांस्कृतिक विचार धाराओं का संवेदनशील मंथन होगा, किसी सकारात्मक समाधान को जन्म दे सकता है।

हमेशा आध्यात्मिक परंपराओं, शिक्षा और सांस्कृतिक आदान-प्रदान का संगम प्रस्तुत करता रहा है। सैक्स ने कहा कि यह शहर प्राचीन ज्ञान का मूल घर था और मैं चाहता हूं कि दुनिया जान सके कि यह जगह मानवता के लिए कितनी महान है, क्योंकि मेरा मानना है कि हम सब इसमें साथ हैं।

ऐसी बैठक की मेज़बानी करके, सैक्स भारत को एक ऐसा मंच प्रस्तुत करते हुए दिख रहे हैं ,जो भू-राजनीति और अर्थव्यवस्था से परे सभ्यतागत मूल्यों पर संवाद को बढ़ावा दे। यह विचार भारत के अपने कूटनीतिक संदेश-जैसे वसुधैव कुटुम्बकम और अंतर्राष्ट्रीय सामंजस्य-के अनुरूप है।

इस प्रस्तावित बैठक में विभिन्न प्रतिभागियों को एकत्रित किया जा सकता है: धार्मिक नेता, दार्शनिक, शिक्षाविद, नीति विचारक और संभवतः नागरिक समाज के प्रतिनिधि। इसका उद्देश्य सिर्फ प्रतीकात्मक संवाद नहीं होगा, बल्कि ऐसा मंच बनाना होगा, जहां विभिन्न परंपराओं-हिंदू, बौद्ध,

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

प्रधानमंत्री ने बुद्ध पूर्णिमा की शुभकामनाएं दीं

नई दिल्ली, 01 मई । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर आज देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए शांति, करुणा और सद्भावना के मार्ग पर चलने का संदेश दिया। उन्होंने सभी से भगवान गौतम बुद्ध के जीवन मूल्यों को अपनाने का संकल्प दोहराने की अपील की।

प्रधानमंत्री ने एक्स पर अपने संदेश में कहा, सभी देशवासियों को बुद्ध

- उन्होंने भगवान बुद्ध के जीवन मूल्यों को अपनाने की अपील की।

पूर्णिमा की असीम शुभकामनाएं। शांति, करुणा और सद्भावना के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देने वाले इस पावन अवसर पर भगवान बुद्ध के जीवन मूल्यों को अपनाने का संकल्प दोहराएं।

उन्होंने इस अवसर पर एक संस्कृत सुभाषित भी साझा किया जिसका अर्थ है कि व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि न तो भीतर और न ही बाहर कोई

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)